<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/99</u> REGD. NO. D. L.-33004/99



सी.जी.-एम.एच.-अ.-29022020-216472 CG-MH-E-29022020-216472

> असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण्ड 4

> PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 82] No. 82] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 27, 2020/फाल्गुन 8, 1941

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 27, 2020/PHALGUNA 8, 1941

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 13 फरवरी, 2020

सं. टीएएमपी/8/2016-टीएमआईएलएल.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा कोलकाता पत्तन न्यास में कार्यरत टीएम इंटरनैशनल लाजिस्टिक्स लिमिटेड के मौज़ूदा दरमानों की वैधता का विस्तार, इसके साथ संलग्न आदेश के अनुसार, करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/8/2016-टीएमआईएलएल

टीएम इंटरनैशनल लाजिस्टिक्स लिमिटेड

आवेदक

<u>गणपूर्ति</u>

- (i). श्री टी.एस.बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)
- (ii). श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

 $1161 \text{ GI/}2020 \tag{1}$

आदेश

(फरवरी, 2020 के 11वें दिन पारित)

यह मामला कोलकाता पत्तन न्यास (केओपीटी) में कार्यरत टीएम इंटरनैशनल लाजिस्टिकस लिमिटेड (टीएमआईएलएल) के मौज़ूदा दरमानों की वैधता के विस्तार से सबंन्धित है।

- 2. अभिलेखबद्ध किये गये कारणों से, इस प्राधिकरण ने फरवरी 26, के अपने आदेश संख्या 2019 टीएएमपी/8-2016/टीएमआईएलएल के द्वारा टीएमआईएलएलके मौज़ूदा दरमानों का विस्तार जून 30,अथवा 2019 टीएमआईएलएल द्वारा दायर किये जाने वाले प्रस्ताव के आधार पर संशोधित दरों के प्रभावी होने तक, जो भी पहले हो, किया था।
- 31.. टीएमआईएलएल ने 1 अप्रैल, वर्ष के प्रशुल्क चक्र के लिये अपने 3 तक के 2022 मार्च 31 से 2019 मौज़ूदा दरमानों को सामान्य संशोधन के लिये नयी प्रशुल्क नीति को अपना प्रस्ताव दायर 2019 अक्टूबर 1 के अंतर्गत 2019 अक्टूबर 17 किया। इस मामले में संयुक्त सुनवाई, 2019 को हुई। हमारे दिसम्बर 19, 2019 के पत्र के द्वारा टीएमआईएलएल से अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण मांगा गया है।
- 3.2. इस संबंध में, टीएमआईएलएल ने अपने 7 जनवरी, 2020 के ई-मेल के द्वारा यह संसूचित किया है कि वे मांगे गये स्पष्टीकरणों का उत्तर तैयार कर रहे हैं और उन्हें कुछ और समय लगेगा। इस प्रकार टीएमआईएलएल ने इस प्राधिकरण को नई दरों के अनुमोदन तक मौजूदा दरमानों का विस्तार करने का अनुरोध किया है।
- 4.1. चूंकि टीएमआईएलएल के मौज़ूदा दरमानों की वैधता 30 जून, 2019 को समाप्त हो गयी है और टीएमआईएलएल के 7 जनवरी, 2020 के ई-मेल के द्वारा किये गये अनुरोध पर सुविचार करते हुए तथा प्रशुल्क में निर्वात से बचने के लिए, यह उपयुक्त समझा जाता है कि टीएमआईएलएल के मौज़ूदा दरमानों की वैधता 1 जुलाई, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक अथवा इस प्राधिकरण द्वारा नई दरों को मंजूरी दिये जाने तक, जो भी पहले हो, विस्तार किया जाये।
- 4.2. तदनुसार, यह प्राधिकरण टीएमआईएलएल के मौज़ूदा दरमानों की वैधता का 1 जुलाई, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक अथवा इस प्राधिकरण द्वारा नई दरों को अनुमोदित किये जाने तक, जो भी पहले हो, विस्तार करता है, जैसा टीएमआईएलएल ने अनुरोध किया है।
- 4.3. यदि टीएमआईएलएल के निष्पादन की समीक्षा के दौरान 01 अप्रैल, 2019 के बाद की अवधि के लिए ग्राह्य लागत और अनुज्ञेय प्रतिफल के अतिरिक्त कोई अधिशेष पाया जाता है तो ऐसे अतिरिक्त अधिशेष को सरकार द्वारा 05 मार्च, 2019 के पत्र संख्या पीआर-14019/20/2009-पीजी (भाग-IV) द्वारा जारी और इस प्राधिकरण द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित महापत्तन न्यासों में बीओटी प्रचालकों के प्रशुल्क निर्धारण दिशानिर्देश 2019 के खंड 3.1.2 के अनुसार निपटाया जायेगा जो पहले प्रशुल्क दिशानिर्देश 2005 द्वारा शासित होते थे।

टी. एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./469/19]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS NOTIFICATION

Mumbai, the 13th February, 2020

No. TAMP/8/2016-TMILL.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing Scale of Rates of the TM International Logistics Limited operating at the Kolkata Port Trust as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No. TAMP/8/2016-TMILL

The TM International Logistics Limited

Applicant

QUORUM

- (i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii). Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 11th day of February 2020)

This case relates to the extension of the validity of the existing Scale of Rates of the TM International Logistics Limited (TMILL) operating at the Kolkata Port Trust (KOPT).

- 2. For the reason as recorded, this Authority vide its Order no. TAMP/8/2016-TMILL dated 26 February 2019 had extended the validity of the existing SOR of TMILL till 30 June 2019 or till the revised rates fixed based on the proposal filed by TMILL comes into force, whichever is earlier.
- 3.1. The TMILL has filed a proposal dated 1 October 2019 for general revision of SOR for the three year tariff cycle from 1 April 2019 to 31 March 2022, under new Tariff Guidelines, 2019. A joint hearing on the case in reference has been held on 17 October 2019. Additional information / clarification has been sought from TMILL vide our letter dated 19 December 2019.
- 3.2. In this regard, the TMILL vide its email dated 7 January 2020 has conveyed that they are preparing the response to the clarification sought and they need some more time. Thus, TMILL has requested this Authority to extend the existing SOR till the new rates are approved.
- 4.1. Since the validity of the existing tariff of TMILL had already expired on 30 June 2019 and considering the request made by TMILL vide its email dated 7 January 2020 and in order to avoid a vacuum in the tariff, it is felt appropriate to extend the validity of the existing tariff of TMILL from 1 July 2019 till 31 March 2020 or till new rates are approved by this Authority, whichever is earlier.
- 4.2. Accordingly, this Authority extends the validity of the existing tariff of TMILL from 1 July 2019 till 31 March, 2020 or till new rates are approved by this Authority, whichever is earlier, as requested by TMILL.
- 4.3. If any additional surplus over and above the admissible cost and permissible return emerges for the period past 1 April 2019, during the review of the performance of TMILL, such additional surplus will be dealt with as per clause 3.1.2. of the Tariff Guidelines, 2019, for determination of tariff for BOT operators operating in Major Port Trusts and previously governed by 2005 Tariff Guidelines issued by the Government vide its letter No. PR-14019/20/2009-PG (PV.IV) dated 5 March 2019 and notified by this Authority in the Gazette of India.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./469/19]